THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, NOVEMBER 13, 2007

3 new police stns to Greater Noida's aid

Lalit Kumar | TNN

Greater Noida: After growing crime rates hobbled the growth potential of Greater Noida, its time for better and increased and better policing seems close on the horizon.

At a review meet of departments of three revenue divisions at Meerut on Monday, state cabinet secretary, Shashank Shekhar Singh, agreed to the setting up of three new police stations in Greater Noida. The proposal had been put up at the meet by Noida police chief, A S Ganesh, who also returned with a sanction of Rs 1.10 crore for modernizing the Surajpur police control room there.

Revealing this, Ganesh told this correspondent that the "Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has also agreed to construct the buildings and infrastructure for the police stations. The authority is very eager that the law and order climate be improved in Greater Noida so that more people come to live there at the earliest. Together, GNIDA and the police have drawn up a policing master plan."

One new police station is to come in Greater Noida's Knowledge Park I, which is an educational hub. The police say there are 30,000 students in the area, and another 50,000 odd are likely to be added as 72 new technical colleges will come up there in a year or two. This is important since most of the prominent law and order situations, in the recent weeks, have involved Greater Noida students.

Another police station will come up in Ecotech I, within which parts of Surajpur, Bisrakh and Kasna police station areas will be included. The third police station will be Ecotech III which will include mainly the areas around the Gautam Buddh University and the proposed IT Park, said Ganesh. "The GNIDA has decided to give the police a total of two acres of land for nine new police stations with the remaining six to come up after the current three. The police control room at Surajpur will now also be computerised fully. For instance, there will be a computerised voice logging system. Also, every police car's location will be seen on the screen in real time. This will help us reduce the time taken for police cars to reach the site of a crime," he said.

lalit.kumar@timesgroup.com

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 27, 2007

Metro line back on track?

Sheila Optimistic About Gr Noida Link, To Meet Mayawati

Megha Suri & Abantika Ghosh | TNN

New Delhi: PM Manmohan Singh's assurance to Mayawati about the airport at Greater Noida may be good news for Noida residents in more ways than one. The airport's viability being closely linked with the Delhi-Noida Metro link means that Delhi government's resistance to the Metro on account of initial running losses may end.

Sheila Dikshit

CM Sheila Dikshit said: "We are looking at it very positively and the issue is likely to come up for discussion when I meet Mayawati. I have already asked for a meeting with her. Our earlier resistance was because the link required us as well as the Central government to make a heavy financial commitment. Further, the Mulayam Singh government minister who had come for the talks did not quite know his facts. They said they will get back to us but never did."

Sources said that UP government was willing to bear the construction cost of Metro, including on the 8-km stretch within Delhi. But as a 49% stakeholder in DMRC, Delhi government was reportedly not willing to shoulder the initial losses. "Any Metro system breaks even only after 15-20 years. The Delhi government — after the disputes with UP over issues like water supply for Sonia Vihar, bus service and the Games Village was not willing to bear the losses. Now that the bus service has resumed, the Games Village issue is resolved and there is optimism about more water for Sonia Vihar, the government may change its stand," said a source.

With the GMR group investing Rs 300 crore in the Connaught Place-IGI Metro link, the PM's positive response to the Greater Noida airport project has also given rise to speculation that whichever company develops it, may be asked to pitch in for the Metro project also.

DMRC, for its part, is working on a detailed project report (DPR) for developing a light rail transit system from Noida sector 32 till Pari Chowk in Greater Noida, where the international airport is proposed. "We are preparing a DPR for the 29-km stretch till the airport site, which will be submitted to Noida administration by the end of June. DMRC has only been asked to prepare the report as of now," said C B K Rao, director (planning and projects) of DMRC.

But even if the project is found to be feasible, the construction may or may not be carried out by DMRC. The main difference between a light rail transit system and MRTS — which is coming up in Delhi — is capacity. While an MRTS can carry up to 60,000 passengers per hour, a light rail transit system can only take up to 30,000. Sources said that since the population density between Noida and Greater Noida is not too much, the latter will be more feasible.

As a part of Phase 2, the Delhi Metro network is traversing a distance of 7 km into Noida till the city centre in sector 32. This project is being funded by the Noida administration to the tune of 80%. The Union government will foot 20%, while the rolling stock will be provided by DMRC.

megha.suri@timesgroup.com
abantika.ghosh@timesgroup.com

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2008

वक्त से पहले मेट्रो नोएडा में!

जून 2009 था डीएमआरसी का लक्ष्य, दिसंबर 08 तक रूट पर होगी मेट्रो

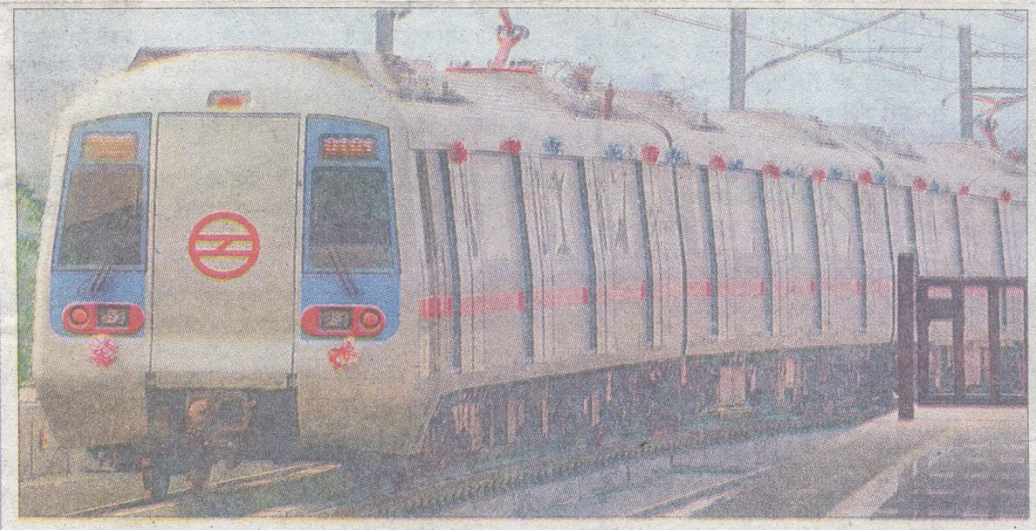

यह साल शहर के लोगों के लिए कई सौगात लेकर आ रहा है। विकास की कई बड़ी परियोजनाएं इसी वर्ष पूरी होने वाली हैं, तो कई का शिलान्यास होगा। उत्तर प्रदेश के इस 'लाडले' शहर के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आ रही है दिल्ली मेट्रो। अपने शहर में साल के अंत तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। निर्धारित समय से छह महीने पहले! दिल्ली में सफलता के बाद बारी नोएडा की है। गुड़गांव और गाजियाबाद से पहले मेट्रो का रुख नोएडा की ओर है। इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा और निजी बसों की धक्का-मुक्की व जाम से मिलेगी मुक्ति। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदूषण का स्तर घटेगा और लोगों का समय भी बचेगा। एक अनुमान के मुताबिक मेट्रो चालू होने से सड़कों पर रोजाना चल रहे दो लाख वाहनों का दबाव घटेगा। लोगों की सहूलियत के लिए नोएडा में बनने वाले सभी छह स्टेशनों में पार्किंग की सुविधा भी होगी। न्यू अशोक नगर से मोरना क्रासिंग सेक्टर 32 तक चलने वाली मेट्रो रेल लोगों को वातानुकूलित सुहाने सफर का अहसास कराएगी।

प्रोजेक्ट का लक्ष्य

नोएडा में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। शासन ने शहर में मेट्रो रेल की मंजूरी 7 दिसंबर 2005 को दी थी। परियोजना का मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू 4 अप्रैल 2006 को हुआ था। न्यू अशोक नगर, गोल चक्कर, नया बांस, सेक्टर 16, अट्टा, सेक्टर 37 क्रासिंग, गोल्फ कोर्स के रास्ते सेक्टर 32 मोरना क्रासिंग तक बन रही मेट्रो रेल के ट्रैक के साथ कुल छह स्टेशन बनाए जा रहे हैं। डीएमआरसी ने काम को पूरा करने का लक्ष्य जून 2009 का रखा था, लेकिन अब यह दिसंबर 2008 में ही पूरा हो जाएगा। शहर में 55 फीसदी से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

बेहतर तालमेल

प्राधिकरण और डीएमआरसी के बीच बेहतर तालमेल के चलते मेट्रो रेल परियोजना को पंख लग गए हैं। परियोजना की राह में आ रही हर अड़चन को दूर करने के लिए हर महीने नोएडा के सीईओ की अध्यक्षता में प्राधिकरण के बिजली, पानी, सीवर, उद्यान, बीएसएनएल और पावर कारपोरेशन की

राष्ट्रमंडल खेलों तक शहर में बनेंगी गगनचुंबी इमारतें

नोएडा, संवाददाता : राष्ट्रमंडलीय खेल के समय तक एक्सप्रेस वे पर गगनचुंबी इमारतों का नजारा देखने को मिलेगा। मेट्रो रेल, स्पोर्ट्स सिटी की चमक-दमक के बीच 30 से 35 मंजिला इमारतें सिंगापुर का अहसास कराएंगी।

इस बाबत प्राधिकरण ने बिल्डरों का नक्शा पास कर दिया है। अब बिल्डर सौ मीटर ऊंचाई तक भवन बना सकेंगे। इसके साथ नोएडा में अधिकतम 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने की बंदिश खत्म हो गई है, लेकिन गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए बिल्डर को एयरपोर्ट अथार्टी, इंवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, फायर स्टेशन की एनओसी और नेशनल बिल्डिंग कोड से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 16 दिसंबर 2006 की नई भवन नियमावली का असर अब नोएडा में दिखना शुरू हो गया है। बिल्डरों को 100 मीटर तक ऊंची इमारत बनाने की एनओसी मिल गई है। अब सिर्फ इन भूखंडों पर काम शुरू किया जाना है। प्राधिकरण ने सेक्टर-44, 126, 132, 137, 96, 97, 98 में 2 से लेकर 25 एकड़ तक के तकरीबन सौ भूखंड बिल्डरों को आवंटित किए हैं। इन्हीं भूखंडों पर नोएडा, गगनचुंबी इमारतों का शहर बनेगा। एसोटेक, यूनीटेक, सुपरटेक, जेपी, आम्रपाली, गौरसंस और आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डर इसे साकार करेंगे। ये इमारतें वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले ही बनकर तैयार हो जाएंगी। भवन प्रकोष्ठ ने अब तक ऐसे दस बड़े भूखंडों का नक्शा पास कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से ग्रुप हाउसिंग और आईटी की गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं। सिटी स्काई लाइन ऑफ इंडिया की शोध संस्था इंडस एनालिटिक्स ने निवेश के लिहाज से गुड़गांव से नोएडा को बेहतर माना है।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर, 2007

प्राधिकरण खुद कराएगा नाइट सफारी का निर्माण

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : महत्वाकांक्षी परियोजना नाइट सफारी का जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकरण ने अपने पूर्व के निर्णय में बदलाव करते हुए खुद निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रस्तावित नाइट सफारी के समीप 150 एकड़ में टूरिज्म व इंटरटेनमेंट जोन विकसित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पहले प्राधिकरण ने किसी प्राइवेट एजेंसी को निर्माण का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया था। 10 दिसंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में उक्त प्रस्ताव रखा जाएगा। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस माह तक सुप्रीम कोर्ट से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना को साकार करने के लिए कवायद तेज कर दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 277 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीन साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्राधिकरण के चेयरमैन व मुख्य कार्यपालक अधिकारी ललित श्रीवास्तव ने बताया कि तीन माह पूर्व केंद्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण से नाइट सफारी को मंजूरी मिलने के बाद सारी अड़चनें दूर हो गई थीं। पर्यावरण की दृष्टि से नाइट सफारी को इस माह के अंत उच्चतम न्यायालय से भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कवायद शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट सफारी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने वाले बर्नाड एंड हैरीसन के साथ परियोजना के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि नाइट सफारी के निर्माण का जिम्मा किसी प्राइवेट एजेंसी को न देकर प्राधिकरण खुद कराए। इससे निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा प्रस्तावित नाइट सफारी के समीप 150 एकड़ में टूरिज्म व इंटरटेनमेंट जोन विकसित किया जाएगा। इसे किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि नाइट सफारी से उतनी ज्यादा आमदनी होने की संभावना नहीं है, जिससे उसका खर्च वहन किया जाएगा। इसलिए टूरिज्म व इंटरटेनमेंट जोन से होने वाली आमदनी को नाइट सफारी पर खर्च किया जाएगा। 10 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में पूर्व निर्णय के बदलाव का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सीईओ ने बताया कि बोर्ड से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रोजेक्ट के डिजाइन व तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विदेशी जानवरों के अनुकूल वातावरण आदि तैयार करने की जिम्मेदारी बर्नाड एंड हैरीसन को दिया जाएगा। उन्होंने बताया सिंगापुर में विश्व के प्रथम नाइट सफारी का डिजाइन बर्नाड एंड हैरीसन ने तैयार किया था।

कामर्शियल व फाइनेंसियल हब के लिए स्थान चिन्हित

ग्रेटर नोएडा, सं : औद्योगिक व वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने पर्थला खंजरपुर गांव के पास सवा सौ हेक्टेयर भूमि पर कामर्शियल व फाइनेंशियल हब के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए दिसंबर के अंत तक टेंडर निकाले जाएंगे। यह दोनों सेक्टर 130 मीटर चौड़ी सड़क होंगे। इन सेक्टरों के ग्रेटर नोएडा में बनने से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि देश की नामी कंपनी इनमें अपना आफिस खोल सकेंगी। इससे शेयर, म्यूचुअल फंड व इंश्योरेंस के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, JULY 25, 2008

Noida allows up to 100% coverage in basements

TIMES NEWS NETWORK

Noida: In an important development, the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) has now allowed house owners in the city to construct basements up to 100 per cent of the area covered by the ground floor of the house.

However, these will be subject to guidelines under the National Building Code, and bylaws of NOIDA. For instance, basements will have to have more than one entrance and exit. No kitchens and bathrooms, and such facilities, will be allowed to be constructed in the basements. The height of the basement should not be less than 7 feet. The distance between the basement and the boundaries of a neighbouring house has also been specified, as has been the setback. It was also decided that allotments of cancelled residential plots can now be restored within a period of three years. There will be no transfer fee if a house is transferred to the daughter-in-law or son-in-law.

toireporter@timesgroup.com

Noida bylaws

नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2007

नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी और लखनऊ में स्टेडियम बनेगा

- मुख्यमंत्री ने की घोषणा, आरपी व पीयूष को कांशी राम खेल पुरस्कार से सम्मानित किया

आरपी सिंह को पुरस्कृत करतीं मुख्यमंत्री।

कानपुर, जागरण संवाददाता : ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए अब सूबे का अकेला स्टेडियम नहीं रहेगा। रविवार को यहां भारत व पाकिस्तान मैच की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनवाने और नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना का ऐलान किया।

तीसरे वनडे मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने आईं मुख्यमंत्री मायावती ने घोषणा की कि लखनऊ में जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। यह स्टेडियम सभी तरह की सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा उन्होंने नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी बनवाने की भी घोषणा की। इस सिटी में सभी खेलों की आधुनिकतम सुविधाएं होंगी, ताकि राज्य के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सके। उन्होंने ट्वेंटी-20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे मध्यम गति के तेज गेंदबाज आरपी सिंह व लेग स्पिनर पीयूष चावला को प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पहले मान्यवर कांशी राम खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार के रूप में दोनों खिलाड़ियों को स्वर्णिम शील्ड व दस-दस लाख रुपये की राशि दी गई। आरपी ने मुख्यमंत्री को 'टीम इंडिया' के सभी खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित बल्ला भेंट किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत में राज्य की खेल गतिविधियों को और बढ़ाने की बात कही।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, AUGUST 28, 2007

Noida e-registers property records

Lalit Kumar | TNN

Noida: In what is regarded as a first among development authorities in UP and the national capital region, Noida has computerised the records of all its residential, commercial and industrial properties.

This means the property number, block, sector and area of the plot, the name of the allottee, the address and dates of allotment, lease deed and taking possession besides details of mortgages and transfers of 68,546 properties in Noida, are now available on the website, *www.noidaauthorityonline.com*.

Revealing this, NOIDA CEO Balvinder Singh said: "We have the complete details of 27,176 residential and group housing plots, 27,873 houses including flats and 13,497 commercial, industrial and institutional properties. The details of the dues for about 7,000 plots, which have not been paid, will be put on the website within three days. The position of properties with 'no dues' will be on the website within 15 days." He said all the allottees have been given a registration ID to view their property's details.

Significantly, the allottees can now make online payments of their dues, to any branch of any of the 15 banks specified by Noida. Singh said: "In the interests of transparency and preventing corruption, the current status of all ongoing Noida projects will be available on the website."

Besides this, a list of frequently asked questions (FAQ) has been put on the website. This includes information on all the forms and formats required for transfers, indemnity bonds and affidavits among other things. Besides any complaints or suggestions can directly be mailed to *ceo@noidaauthorityonline.com*.

lalit.kumar@timesgroup.com

C'wealth makeover for Gzb

Traffic Master Plan In A Month, Metro MoU To Be Signed On Wed

Lalit Kumar | TNN

Ghaziabad: A sound and extensive traffic infrastructure in the city, foreign firms investing billions in state-of-the-art housing complexes, knowledge park and an IT hub — all connected by the Metro — and seven-storeyed parking lots built across the city by Singapore firms.

This is not a list of distant urban dreams but a potential close to reality if the state government's latest plans take shape.

At a board meeting of the Ghaziabad Development Authority (GDA) on Saturday, Uttar Pradesh principal secretary (housing) Shankar Agarwal directed the GDA chief architect and town planner, S K Zaman, to draw up a master plan for city traffic within a month. He made it clear that the plan recommendations, which should be valid for at least 20 years, will be implemented before the start of the Commonwealth Games. This will include widening of existing roads and construction of new roads, necessary flyovers and underpasses among other things.

The board also decided to issue a cheque of Rs 130 crore to the Delhi Metro Rail Corporation, for the implementation of the first phase of the Metro in Ghaziabad. Both the payment and the signing of the MoU for the first phase are scheduled for Wednesday.

Revealing this, GDA vice-chairperson S K Dwivedi said: "The board has also cleared a proposal for setting up a 450-acre SEZ near Modinagar. One SEZ is already planned in Ghaziabad to be set up by converting Loni's Tronica City. A 300-acre knowledge park and a 250-acre IT hub are also to come up near the proposed Hi-tech city venture covering a total of 3,000 acres. Land in the IT hub will sell at 40% less than the cost of residential land in the area, according to state norms. The work on the IT hub and knowledge park is expected to be completed in three months," he added.

TOI

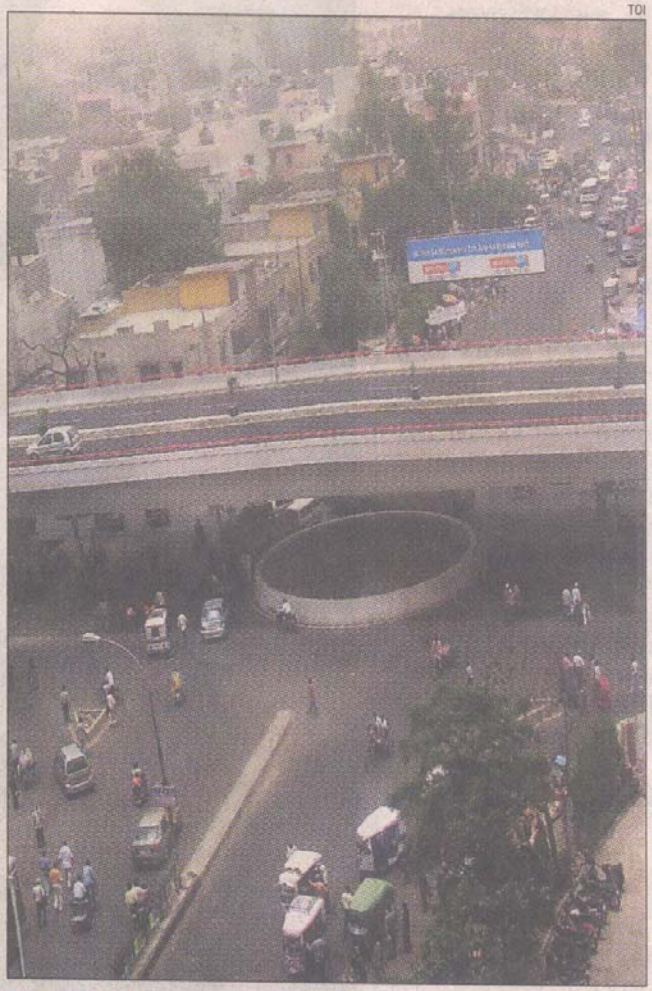

CHANGING FACE: Flyovers and underpasses, besides new roads, will be part of the traffic master plan that GDA is drawing up

> The GDA board cleared plans for construction of new roads, flyovers and underpasses. Besides, work on a 300-acre knowledge park and a 250-acre IT hub is expected to be completed within three months

Dwivedi also said: "SITQ, Canada's biggest finance and investment company, has decided to invest $1.6 billion in the Hi-Tech city project.

"The company may also put in another $2 billion through its Singapore subsidiary. SITQ world chief Campbell is expected to visit the site on Wednesday. An advance team had already okayed the deal in principle."

Another major decision taken up by the board was clearing the construction of a six-lane flyway, 3.5-km-long, to bypass Modinagar on way to Meerut. Work on the six-lane expressway that will connect the Meerut Road triple crossing to the proposed Integrated City area, is already underway.

lalit.kumar@timesgroup.com

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, AUGUST 13, 2007

Rules for land acquisition bent for VIPs

Lalit Kumar | TNN

Ghaziabad: When it comes to out of turn allotments of plots for VIPs, the master plan, the designated land use of the plot and its actual market rate do not come in the way.

When former UP minister Shivpal Yadav, brother of former CM Mulayam Singh Yadav, wanted to buy a residential plot of land from the GDA, the authority converted a plot earmarked for a shopping centre into a residential one. Moreover, the 450 m sq plot was sold to Yadav, in the so called "MLA quota", at GDA's residential sector rate of Rs 5,000 per sq m. As a commercial plot, it would have been auctioned for at least Rs 60,000 per sq m at the time.

After news of the transaction began to spread, Yadav was forced to return plot for a refund a year later, on January 1, 2006. The GDA did not convert the land use back to commercial. It auctioned the plot as a residential one, at Rs 21,300 per sq m, notwithstanding the current rates of commercial plots and fact that residential plots had never before been auctioned.

Former GDA board member, Rajendra Tyagi said, "This resulted in Rs 2.20 crore loss to GDA. There is no reason why GDA should not have re-converted plot into a commercial one for re-selling it. Obviously, they were trying to oblige someone."

lalit.kumar@timesgroup.com

Cabinet clearance for Gzb Metro

Lalit Kumar | TNN

Ghaziabad: Work on the first phase of the Metro in Ghaziabad has begun with the UP cabinet clearing the Rs 260-crore project. Although some details are being worked out —like ensuring that the MoU with the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) is on the same terms as the one signed between DMRC and the Noida Authority—highly-placed UP government sources said: "This will not affect the start of the work".

The state government has also decided to build an inter-state bus terminal at Kaushambi where the first stop of the metro will be located, said UP transport minister Ramachal Rajbhar on Tuesday.

Rajbhar added that more than four dozen luxury buses similar to Volvo, with low floors and computerised ticketing, will also be started from this ISBT. Although the ISBT will take almost two years to be operational, the luxury buses will start plying by the first quarter of next year.

These 'disabled friendly' buses will ply mainly on Ghaziabad, Noida and Greater Noida roads. These buses will cost about Rs 5 crore which will be paid jointly by the Ghaziabad Development Authority and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation.

According to GDA vice-chairman, S K Dwivedi: "The ISBT planned at Kaushambi will become a sort of integrated transport hub. It will have provision for parking, cyber cafes, ATMs, restrooms, and other facilities. It will come up next to the Pacific Mall." The Metro in Ghaziabad will be run on an over 2-kilometre-long elevated track in the first phase.

lalit.kumar@timesgroup.com

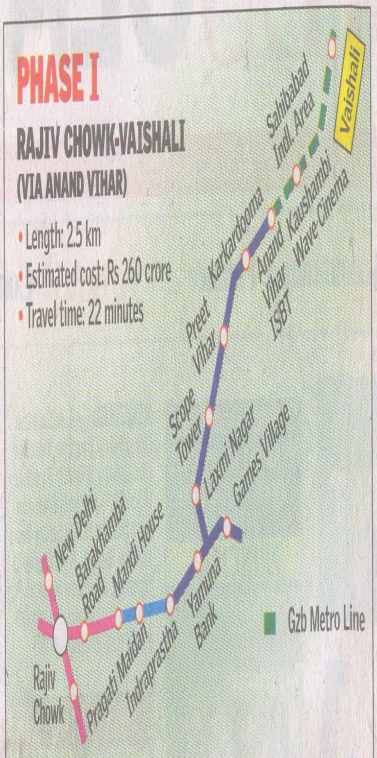

Govt revives bridge project

New Delhi: The Delhi government has revived its Signature bridge project but it is all set to miss out being showcased during the 2010 Commonwealth Games. The government has decided to go for a fresh tender to revive the project.

The bridge planned at Wazirabad as a key highlight with a proposal to develop the riverbanks around the site as a tourist attraction during the 2010 Games, is unlikely to become a reality by then. The project had run into trouble after it was found that at Rs 845.97 crore, the lowest bid amount received for the bridge under a tender was nearly double the initial estimate of Rs 459 crore. TNN

नई दिल्ली, 31 मई, 2007 जागरण सिटी www.jagran.com

ग्रेटर नोएडा से नोएडा व गाजियाबाद पंद्रह मिनट में

तीनों शहरों को जोड़ने के लिए बन रहे हाईवे का निर्माण कार्य शुरू

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : ताज एक्सप्रेस-वे परियोजना की तर्ज पर दो साल पहले प्रस्तावित नोएडा, गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा के बीच एक और हाईवे का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 25 किमी लंबे इस मार्ग का निर्माण कार्य दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा। हाईवे बनने पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा व गाजियाबाद की दूरी मात्र बारह से पंद्रह मिनट में तय की जा सकेगी। अभी तक दोनों शहरों तक पहुंचने के लिए 40 से 45 मिनट का समय लगता है। इस हाईवे पर भी ताज एक्सप्रेस-वे की तरह कोई रेडलाइट नहीं होगी। जहां-जहां गांव पड़ेंगे, वहां रोटरी व फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। करीब पच्चीस किलोमीटर लंबी इस सड़क की चौड़ाई 130 मीटर होगी और इस पर चलने वाले वाहनों की स्पीड लिमिट 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस हाईवे के बनने से नोएडा व गाजियाबाद ही नहीं, हापुड़, मेरठ व मुरादाबाद जाने वालों के लिए भी रास्ता सुगम हो जाएगा। हाईवे का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इस चरण का काम दिसंबर 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क के निर्माण पर करीब सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जोरों पर चल रहा हाईवे का निर्माण कार्य। जागरण

इस परियोजना को जगनपुर गांव के पास ताज एक्सप्रेस-वे से शुरू किया गया है। एशियन पेंट्स कंपनी व इकोटेक एक्सटेंशन, सिंगमा, इंटा-जीटा सेक्टर के बीच से होती हुई तिलपता गांव के पास नोएडा-दादरी मुख्य मार्ग पर जाकर मिल जाएगी। यहां पहला फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ताकि डीएससी रोड पर चलने वाले वाहन इससे प्रभावित न हों। इसके बाद यह सड़क खोदना खुर्द व बिसरख गांव के पास से होते हुए पथला खंजरपुर गांव के पास हिंडन पर पहुंच जाएगी। वहां करीब दो सौ मीटर लंबा पुल बनेगा। पुल बनने के बाद सड़क को नोएडा के सेक्टर 71 में औखला बैराज व सेक्टर 37 से होते हुए आने वाले एमपी-3 मार्ग पर जोड़ दिया जाएगा। इटेड़ा गांव के पास एक फ्लाईओवर बनाकर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से जोड़ा जाएगा।

सड़क के दोनों तरफ चौबीस मीटर चौड़े सर्विस लेन होंगे, ताकि इसके आसपास पड़ने वाले गांवों के लोगों को कोई दिक्कत न हो और हाईवे का यातायात भी प्रभावित न हो। भीड़भाड़, जाम या दुर्घटनाओं से बचने के लिए किसी भी गांव की एंट्री सीधे हाईवे से नहीं दी जाएगी। फ्लाईओवर व रोटरी बनाकर गांवों को हाईवे से जोड़ा जाएगा। फ्लाईओवर व रोटरी भी इस तरह से बनाई जाएंगी कि कई गांवों की एंट्री एक ही प्वाइंट पर जुड़ सके। रोटरी के पास से छोटे-छोटे सर्विस रोड निकालकर उससे गांवों को जोड़ा जाएगा। सड़क के बीच में तीस मीटर चौड़ी जगह कारिडोर के लिए छोड़ी गई है। इसमें मेट्रो व मोनो रेल लाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह सड़क नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद समेत कई शहरों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन दोनों शहरों के लिए जाना तो आसान हो ही जाएगा। बल्कि हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद व उत्तराखंड जाने वाले वहां से बुलंदशहर व अलीगढ़ जाने वालों के लिए भी सफर आसान हो जाएगा। इस सड़क के बनने के बाद गाजियाबाद-दादरी से होते हुए बुलंदशहर अलीगढ़ जाने वाले वाहन दादरी में लगने वाले जाम से बचने के लिए इसी मार्ग से निकलेंगे। इस समय ग्रेटर नोएडा से नोएडा हाईवे होकर दिल्ली जाने में करीब 35 मिनट का समय लगता है, जबकि इस मार्ग से जाने में मात्र 28 मिनट लगेंगे। प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) एसएस रिजवी ने बताया कि हाईवे व डीएसए रोड पर भविष्य में वाहनों के दबाव को देखते हुए 130 मीटर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बनने से दादरी जीटी रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा।

हाईवे का प्रस्तावित नक्शा।

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2007

ग्रेटर नोएडा की हाईटेक सिटी स्कीम निरस्त होगी

◆ मायावती ने मुलायम सरकार का एक और फैसला पलटा

लखनऊ, जागरण ब्यूरो : मुलायम सिंह सरकार के समय के एक और महत्वपूर्ण फैसले को बदलते हुए मायावती सरकार ने बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा की उत्तम स्टील टाउनशिप और लखनऊ की अंसल हाईटेक सिटी योजनाओं को रद्द करने का फैसला किया। सरकार ने दोनों विकासकर्त्ताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं तथा आवास विभाग को निर्देश दिया है कि पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में जो भी खामियां रही हैं उन्हें दूर करने के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल के विचारार्थ पेश किया जाए।

यह फैसला मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक किया गया। जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव शशांक शेखर ने शाम को पत्रकारों को दी। मंत्रिमंडल ने इसके अलावा खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 80 रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये कर दी है तथा प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी डेंटल कालेजों को फिर से छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध करने के लिए विधान मंडल के इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाने का निश्चय किया है।

बताया गया कि मंत्रिमंडल ने हाईटेक सिटी परियोजनाओं को रद करने का फैसला औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन परियोजनाओं को मंजूर करने में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम मानकों का पालन नहीं किया जिसके कारण इसमें तमाम खामियां रह गई हैं। मंत्रिमंडल ने समिति की रिपोर्ट को ■ शेष पृष्ठ 2 कॉलम 2पर

ग्रेटर नोएडा की हाईटेक...

यथावत स्वीकार कर लिया है। शशांक शेखर ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लखनऊ के सुलतानपुर रोड पर प्रस्तावित लगभग दो हजार एकड़ की अंसल हाईटेक सिटी और ग्रेटर नोएडा के फेज दो में स्थित उत्तम स्टील एसोसिएट्स हाईटेक सिटी की लगभग ढाई हजार एकड़ की परियोजनाओं में निवेश सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति ने यह भी कहा है कि विकासकर्ताओं ने कंपनी के पास भूमि उपलब्ध न होते हुए भी प्रीलांचिंग के नाम पर जन सामान्य से धनराशि जमा कराई जबकि इस धनराशि की कोई गारंटी नहीं रहती। ग्रेटर नोएडा परियोजना के बारे में कहा गया है कि उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स परियोजना का प्रस्ताव जब तैयार हुआ था तो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिसूचित नहीं था। नवंबर 2006 में प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ले लिया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 2021 के अनुरूप जो योजना तैयार की गई है उस मानक में यह ठहर नहीं पाता है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2007

गाजियाबाद तक मेट्रो के लिए 900 करोड़ मंजूर

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : गाजियाबाद में मेट्रो का आना तय हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में बढ़ी हुई दर को मंजूरी दे दी। मेट्रो के लिए अलग से 900 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, महानगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 400 करोड़ रुपये से ओवर ब्रिज व अंडरपास का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा आवासीय सेक्टर दरों में प्राधिकरण ने 20 से 30 फीसदी की वृद्धि की है। दिल्ली स्थित राजस्थान भवन में सोमवार को आयोजित 113वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2007-08 के लिए एक हजार करोड़ की आय व 1900 करोड़ रुपये के खर्च के बजट को मंजूरी दे दी गई। प्राधिकरण उपाध्यक्ष एसके द्विवेदी ने बताया कि बजट में आय से अधिक खर्च रखने का कारण वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर गाजियाबाद की कायापलट की योजनाएं हैं। महानगर में मेट्रो विस्तार के 900 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। शेष पृष्ठ 2 कॉलम 3 पर

गाजियाबाद तक मेट्रो...

वैसे मेट्रो चरणबद्ध तरीके से आएगी, लेकिन इसके लिए खर्च का पहले से प्रावधान कर दिया गया है। इस बीच यह भी तय हुआ है कि मेट्रो रेल प्रबंधन ने जो नए रेट का आधार दिया है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पहले चरण में आनंद विहार से वैशाली तक मेट्रो का विस्तार होना है। उन्होंने बताया कि मेट्रो विस्तार के लिए जीडीए बिल्डरों से मेट्रो सेस वसूलेगा। मुख्य रूप से हाईटेक व इंटीग्रेटिड सिटी की दिशा में आगे आ रहे बिल्डरों से 320 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मेट्रो सेस के रूप में वसूली होगी। उन्होंने बताया कि 400 करोड़ रुपये महानगर में चौराहे-तिराहे पर फ्लाईओवर आदि पर खर्च किए जाएंगे। मेरठ रोड से हापुड़ रोड बाईपास के बीच प्रस्तावित सड़क के स्टीमेट का आईआईटी, दिल्ली या फिर रुड़की से अध्ययन कराया जाएगा। इंदिरापुरम विस्तार योजना में फाइव स्टार व थ्री स्टार होटल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, OCTOBER 10, 2008

TIMES CITY

KGP corridor work starts in '09

High-Speed Expressways Will Take Load Off Internal Roads

Dipak Kumar Dash | TNN

New Delhi: Two high-speed corridors, which will significantly de-clog the city's internal roads of outbound traffic and trucks, are likely to be ready by 2012. While the western peripheral expressway (Kundli-Manesar-Palwal) is scheduled to be completed by the end of next year, the eastern peripheral expressway (Kundli-Ghaziabad-Palwal) will be complete by mid 2012.

The National Highways Authority of India (NHAI) recently held the pre-bidding conference for the second project and officials said that the work on this stretch will start by June-July 2009.

The country's eight leading bidders shortlisted for the project participated in the conference. NHAI officials said the bidding process would be completed by the end of 2008. "We will give six months time to the selected bidder for the financial closure for this Rs 2,675-crore project. Over 80% of the land acquisition for this new alignment has been completed," said a senior official.

The 135-km long access controlled expressway to be built on build-operation-transfer basis (BOT) takes off from NH-1 in Kundli (Haryana), crosses Yamuna river near Mawikalan, river Hindon near Sharfabad, NH-58 near Duhai, NH-24 near Dasna, NH-91 near Beelakbarpur, Kasna-Sikandrabad road near Sirsa, re-crosses Yamuna near Fajjupur Khadar, Atali-Chinsa near Maujpur and meets NH-2 beyond Palwal. It will pass through five districts — Sonipat, Faridabad in Haryana and Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh.

NHAI officials said the speed limit for this green field project would be 120 kmph. The project includes construction of three major bridges — two across Yamuna and one across Hindon river besides 43 other bridges over canals and drains. Nevertheless, there will be as many as 59 underpasses for the safe movement of pedestrians.

For locals, the developer will construct service roads of about 90 km, which will provide connectivity between different areas along the expressway.

The 135.6-km long four-lane western peripheral expressway, being built at investment of Rs 2,545 crore starts from NH-1 near Kundli (Sonipat) crossing NH-10 at west of Bahadurgarh, crossing NH-8 at Manesar (Gurgaon) and joining NH-2 near Palwal (Faridabad).

dipak.dash@timesgroup.com

STEERING CLEAR OF TRAFFIC MESS

Kundli-Ghaziabad-Palwal/ Eastern Peripheral Expressway

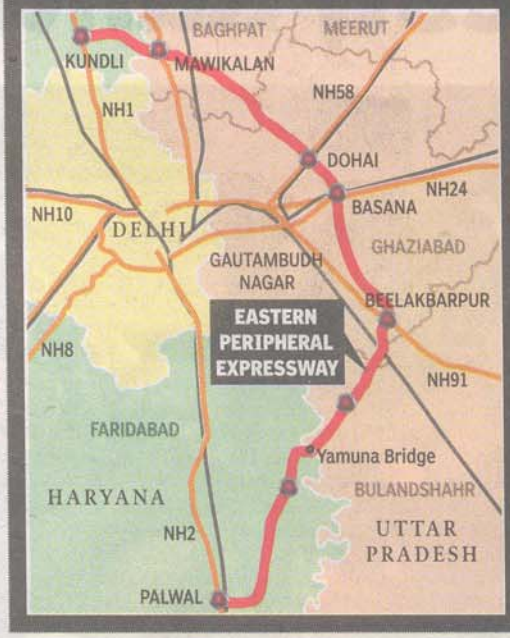

- Total length | 135 kilometres
- Project cost | Rs 2,675 crore
- Lanes | 6-lane carriage way with 8-lane structure for future expansion
- Areas covered | Sonipat, Faridabad in Haryana; Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in UP
- Proposed speed limit | 120 kmph
- Work scheduled to start | June-July 2009
- Scheduled completion of project | June-July 2012
- Toll plazas | 02, toll booths | 07
- Expected vehicular movement | 40,000 PCU by 2021. 1 lakh by 2021
- Concession period | 20 years including 3 year construction period
- Bridges and underpasses | 2 across Yamuna and one across Hindon. 43 other bridges. 59 underpasses.
- Interchanges | 1 each at NH-1, NH-2, NH-24, NH-58, NH-91, SH-57,
- Kasna-Sikandrabad road/Taj Expressway, Atali-Chainsa Road

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

द्वारा

नववर्ष के

शुभ अवसर पर

दुर्बल आय वर्ग

के लिये

दो कमरों की

आवासीय योजना

कोयल इन्कलेव

आवासीय योजना

योजना प्रारंभ की तिथि 10/01/2008

योजना की अंतिम तिथि 10/02/2008

कोयल इन्कलेव योजना की स्थिति एवं मुख्य आकर्षण :-

1. यह योजना भोपुरा गांव के पास मुख्य लोनी मार्ग पर स्थित है, जो देश की राजधानी दिल्ली के सन्निकट है।
2. उक्त योजना को लगभग 90 एकड़ में विकसित किया जाना है।
3. उक्त योजना में जन सुविधाओं हेतु जैसे - सड़कें, सीवर, पार्क, जलापूर्ति, विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था की जायेगी।
4. योजना में सामुदायिक सुविधाओं के रूप में सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सरी/प्राईमरी विद्यालय, पुलिस पोस्ट, पोस्ट ऑफिस आदि का प्रावधान किया जायेगा।
5. योजना को पर्यावरण के दृष्टि से हरा-भरा रखने हेतु ग्रीन बेल्ट एवं पार्क आदि को भी विकसित किया जायेगा।
6. योजना में प्रथम बार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों हेतु दो कमरों के चार मंजिले भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
7. प्रत्येक भवन में अन्दर दो कमरे, किचन, शौचालय एवं स्नानघर का प्रावधान किया गया है।

आवेदन कैसे करें :

पूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र 100/- के भुगतान पर दिनांक 10/1/2008 से विजया बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पंजीकरण राशि केवल ड्राफ्ट द्वारा विजया बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की इन्हीं शाखाओं में दिनांक 10/2/2008 तक बैंक के कार्य समय में किसी भी कार्य दिवस में जमा किए जा सकते है

विजया बैंक की शाखाएं : • **गाजियाबाद** : 84 नवयुग मार्केट, **इन्द्रापुरम**: अहिंसा खण्ड-II, **हापुड़**: अपोजिट नगरपालिका • **नई दिल्ली**: बाराखम्बा रोड़, कनाट प्लेस, **करोल बाग**: पदम सिंह रोड़, **डिफेन्स कालोनी**: अपोजिट मूलचन्द अस्पताल, **दिल्ली कैन्ट**: गोपीनाथ बाजार, नेहरू प्लेस: चिराग ऐनक्लेव, **शाहदरा**: लोनी रोड़, **पश्चिम विहार**: सी/68 एलआईसी कालोनी, **चॉन्दनी चौक**: मोती सिनेमा कम्पाउन्ड, श्रेष्ठ विहार (विज्ञान विहार), **विकास मार्ग**: राजधानी ऐनक्लेव, मुनिरका, कृष्णा पार्क, पटपड़गंज प्लाट न. 5, IP एक्सटेन्शन, **रोहिणी**: सेक्टर-3 ईएसएस प्लाजा, **रामनगर**: पहाड गंज, • **नोएडा**: A-5, सेक्टर-19, एसएसआई नोएडा-B/12, सेक्टर-60 • **मोदीनगर**: दिल्ली-मेरठ रोड़ • **अलीगढ़**: 13/6, जी.टी. रोड • **लखनऊ**: 31/49, एम.जी. मार्ग मेफेयर बिल्डिंग हजरत गंज • **मेरठ**: 127-128, सदर बाजार, रंगराज स्ट्रीट • **मुरादाबाद**: A/20, गांधी नगर, दिल्ली रामपुर रोड़ • **आगरा**: न. 1426, जीओनी मंडी • **वाराणसी**: 48/141, लुक्सा रोड • **कानपुर**: हीरा सन्स हाउस, 74/276, हेसली रोड • **बुलन्दशहर** : न.-2, रोडवेज बस स्टैंड रोड • **इलाहाबाद**: न.:5, बेली रोड नया कटरा • **झांसी**: कचेरी चराहा • **गोरखपुर**: बैंक रोड • **बरेली**: 41, सिविल लाईन्स श्याम गंज • **सहारनपुर**: प्रताप मार्केट • **हरिद्वार**: गोविन्दपुरी, रामपुर मोड • **देहरादून**: महंत लक्ष्मी दास रोड • **चंडीगढ़**: एलआईसी बिल्डिंग सेक्टर-17B • **जयपुर**: अहिंसा सर्कल, सुभाष मार्ग • **गुड़गांव**: पायल सिनेमा काम्पलेक्स सेक्टर-14 • **फरीदाबाद**: प्लॉट न. R-4 एनएचएस एनआईटी

पंजाब नैशनल बैंक की शाखाएं: • **गाजियाबाद** : मोहन नगर, • अम्बेडकर रोड, नेहरू नगर, कौशाम्बी, वीएमएलजी सुशीला कॉलेज, लोनी, एकेपी विजय नगर, गोविंद पुरम, राज नगर • **हापुड** : हापुड़ मेन • **मोदीनगर** : मोदीनगर मेन • **मेरठ** : अबु लेन, मेरठ कैंट, एक्क रोड • सेक्टर-2, शास्त्री नगर, बागपत रोड़ • **बागपत** : जैन मोहल्ला, बड़ौत • **मुजफ्फनगर** : मुजफ्फनगर सिटी, मुजफ्फर नगर न्यू मंडी • **सहारनपुर** : न्यू आवास विकास, सिविल लाईन्स • **रूड़की** : सिविल लाईन्स • **हरिद्वार** : अहमदपुर • **देहरादून** : क्लाक टावर • **बुलन्दशहर** : सिविल लाईन्स • **आगरा** : संजय प्लेस • **अलीगढ़** : सिविल लाईन्स • **लखनऊ** : गोमती नगर • **इलाहाबाद** : सिविल लाईन्स • **मुरादाबाद** : सिविल लाईन्स • **फरीदाबाद** : एनआईटी • **गुड़गांव** : गुड़गांव मेन • **दिल्ली / नई दिल्ली** : संसद मार्ग, दिलशाद गार्डन, यमुना विहार, प्रीत विहार • **गौतम बुद्ध नगर** : नोएडा सेक्टर-27, • ग्रेटर नोएडा, अल्फा सेक्टर • **वाराणसी** : नीची बाग • **झांसी** : झांसी सिटी • **कानपुर** : माल रोड़ • **गोरखपुर** : बैंक रोड • **बरेली** : सिविल लाईन्स • **सोनीपत** : सोनीपत मेन • **करनाल** : जी.टी. रोड करनाल

	योजना की	भवनों का	पंजीकरण राशि + पंजीकरण शुल्क रू. 40/- भवनों

www.gdaghaziabad.com

बैंक से सम्पर्क हेतु दूरभाष संख्या-विजया बैंक: 0120-2790382, 2791419, पंजाब नेशनल बैंक: 0120-2657101-02-03 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एक सुन्दर शहर - हमारा संकल्प

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, OCTOBER 10, 2008

TIMES CITY

KGP corridor work starts in '09

High-Speed Expressways Will Take Load Off Internal Roads

Dipak Kumar Dash | TNN

New Delhi: Two high-speed corridors, which will significantly de-clog the city's internal roads of outbound traffic and trucks, are likely to be ready by 2012. While the western peripheral expressway (Kundli-Manesar-Palwal) is scheduled to be completed by the end of next year, the eastern peripheral expressway (Kundli-Ghaziabad-Palwal) will be complete by mid 2012.

The National Highways Authority of India (NHAI) recently held the pre-bidding conference for the second project and officials said that the work on this stretch will start by June-July 2009.

The country's eight leading bidders shortlisted for the project participated in the conference. NHAI officials said the bidding process would be completed by the end of 2008. "We will give six months time to the selected bidder for the financial closure for this Rs 2,675-crore project. Over 80% of the land acquisition for this new alignment has been completed," said a senior official.

The 135-km long access controlled expressway to be built on build-operation-transfer basis (BOT) takes off from NH-1 in Kundli (Haryana), crosses Yamuna river near Mawikalan, river Hindon near Sharfabad, NH-58 near Duhai, NH-24 near Dasna, NH-91 near Beelakbarpur, Kasna-Sikandrabad road near Sirsa, re-crosses Yamuna near Fajjupur Khadar, Atali-Chinsa near Maujpur and meets NH-2 beyond Palwal. It will pass through five districts — Sonipat, Faridabad in Haryana and Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh.

NHAI officials said the speed limit for this green field project would be 120 kmph. The project includes construction of three major bridges — two across Yamuna and one across Hindon river besides 43 other bridges over canals and drains. Nevertheless, there will be as many as 59 underpasses for the safe movement of pedestrians.

For locals, the developer will construct service roads of about 90 km, which will provide connectivity between different areas along the expressway.

The 135.6-km long four-lane western peripheral expressway, being built at investment of Rs 2,545 crore starts from NH-1 near Kundli (Sonipat) crossing NH-10 at west of Bahadurgarh, crossing NH-8 at Manesar (Gurgaon) and joining NH-2 near Palwal (Faridabad).

dipak.dash@timesgroup.com

STEERING CLEAR OF TRAFFIC MESS

Kundli-Ghaziabad-Palwal/ Eastern Peripheral Expressway

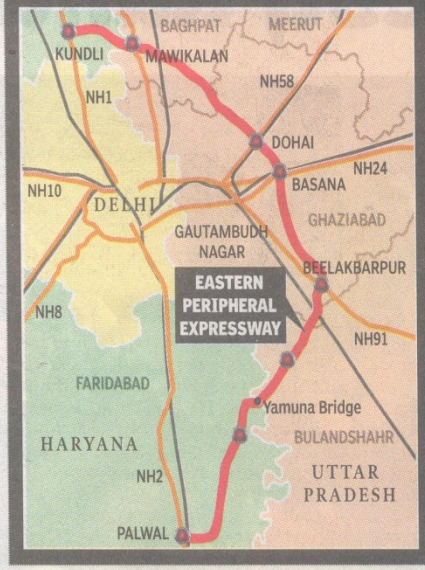

- Total length | 135 kilometres
- Project cost | Rs 2,675 crore
- Lanes | 6-lane carriage way with 8-lane structure for future expansion
- Areas covered | Sonipat, Faridabad in Haryana; Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in UP
- Proposed speed limit | 120 kmph
- Work scheduled to start | June-July 2009
- Scheduled completion of project | June-July 2012
- Toll plazas | 02, toll booths | 07
- Expected vehicular movement | 40,000 PCU by 2021. 1 lakh by 2021
- Concession period | 20 years including 3 year construction period
- Bridges and underpasses | 2 across Yamuna and one across Hindon. 43 other bridges. 59 underpasses.
- Interchanges | 1 each at NH-1, NH-2, NH-24, NH-58, NH-91, SH-57,
- Kasna-Sikandrabad road/Taj Expressway, Atali-Chainsa Road